जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 47 संख्याः 346 प्रभात कोटा, बुधवार 28 सितम्बर, 2022 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अजय माकन-खड़गे ने जयपुर की बगावत पर नौ पेज की रिपोर्ट दी सोनिया गांधी को

गहलोत के खास कारिन्दे, शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। राजस्थान समाप्त होने में अभी समय लगेगा। अजय माकन कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि विद्रोह अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ था तथा सब कुछ उनके निर्देश एवं देख-रेख में चला था।

सूत्रों का कहना है कि क्लीन चिट का प्रश्न ही नहीं है, जैसा कि अधिकांश राष्ट्रीय मीडिया तथा टी.वी. चैनल निष्कर्षतः कह रहे हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ ने आज अशोक गहलोत से दो बार बात की तथा उनसे इस्तीफा देने के लिये कहा, लेकिन समझा जाता है कि उन्होंने यह बात मानने से इंकार कर दिया।

तद्नुसार, वे बड़े नेता, जो 90 से अधिक विधायकों की परेड करा रहे थे, मुश्किल स्थिति में हैं तथा इस पेचीदा स्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं।

बताया जाता है कि सोनिया गांधी उस रात की घटनाओं से बहुत अशांत एवं व्यथित हैं क्योंकि वे गहलोत पर आँख बंद कर के विश्वास करती थीं तथा उन्होंने पार्टी की बागडोर उन्हें सौंपने का मानस बना लिया था।

- **अब गौरतलब बात यह है कि, क्या गहलोत अपने खास कारिन्दों के साथ खड़े रहेंगे या उनकी बलि चढ़ाकर आगे बढ़ेंगे।**
- **कारिन्दों के खिलाफ कार्यवाही, सीधे मु.मंत्री के खिलाफ कार्यवाही मानी जाती है और वैसे भी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि, उस रविवार की रात का सारा ड्रामा गहलोत के निर्देश पर तथा उनकी निगरानी में खेला गया था।**
- **पर, दूसरी ओर उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिन में दो बार कमलनाथ ने गहलोत से बात की तथा इस्तीफा देने की सलाह दी, पर गहलोत राय स्वीकार करने की मनःस्थिति में नहीं थे।**
- **वरिष्ठ नेता व ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटनी को दिल्ली बुलाया गया है और अनुशासन कार्यवाही तय करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।**

सूत्रों ने कहा कि यह सोनिया के लिये पीठ में छुरा भौंकने जैसा कृत्य है।

अजय माकन तथा खड़गे ने अपनी 9 पृष्ठों की रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास भेज दी है जिसमें गहलोत को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है जिन्होंने इसे पूरे घटनाक्रम को उकसाया तथा उन्हें दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।

माकन जब सोनिया गांधी से मिले तो उन्होंने सोनिया से यह बात कह दी तथा इसे अपनी रिपोर्ट में भी अंकित कर दिया।

गहलोत के दाँये तथा बाँये हाथ माने जा रहे लोग जो विधायकों को बहकाने तथा प्रलोभन देने में सक्रिय रहे, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा कर दी गई है। ये हैं- शान्ति धारीवाल, महेश जोशी तथा धर्मेन्द्र राठौड़, जो गहलोत के मनी बैग हैं।

देखना यह है कि गहलोत इस सब पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जो उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे या उनकी कुर्बानी देंगे और आगे बढ़ जायेंगे।

वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, जो ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, आज रात दिल्ली पहुँच रहे हैं तथा उसके बाद ही, गहलोत के इन समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही शुरु होगी।

इस बीच, सचिन पायलट आज शाम दिल्ली पहुँचे क्योंकि अब कार्यवाही का स्थल दिल्ली हो गया है। समझा जाता है कि पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा जो इस पूरे घटनाक्रम में खामोश बने रहे थे तथा अशोक गहलोत के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, भी हटाये जाने वालों की कतार में हैं।

'इस्तीफे स्वीकारने ही होंगे'

जयपुर, 27 सितम्बर (का.सं.)। प्रदेश चल रहे सियासी संकट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि इस समय राजस्थान में प्रशासनिक, वैधानिक और संवैधनिक तीनों प्रकार के संकट पैदा हो गए हैं। संवैधानिक संकट यह है कि विधानसभाध्यक्ष (स्पीकर) को विधायकों ने इस्तीफे सौंपे हैं, ऐसे में इन इस्तीफों को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो इस्तीफे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस

- **वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि, अगर स्पीकर को इस्तीफा भेजा जाता है तो, नियमानुसार उन्हें इस्तीफे स्वीकारने ही पड़ेंगे।**

विधायकों ने आलाकमान के खिलाफ रोष प्रकट करने का माध्यम स्पीकर को जरिया बनाया है। स्पीकर के पास अगर कोई व्यक्ति आकर त्याग पत्र दे देता है तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस के विधायक रोष प्रकट करना चाहते थे तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते। इस ताबड़तोड़ से प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हो गई है। वैधानिक संकट यह है कि सरकार रहेगी या जाएगी। प्रशासनिक संकट यह है कि लंपी फैल रहा है और बाजरा भी नहीं खरीदा जा रहा है।

पहले भी कई बार कई मु.मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला है

गत पचहत्तर साल में से 42 साल गांधी परिवार के पास रहा है अध्यक्ष पद

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। वस्तुस्थिति यह है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गये हैं लेकिन भारत की इस शानदार अतीत वाली पार्टी में ऐसे कई पूर्वोदाहरण है, जब कार्यरत मुख्यमंत्रियों ने राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर, संगठन के सर्वोच्च पद का दायित्व ग्रहण किया है।

- **निजलिंगप्पा ने कर्नाटक के मु.मंत्री पद से त्यागपत्र देकर 1968-69 में कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली थी।**
- **1954 में प्र.मंत्री प. नेहरू ने सौराष्ट्र के मु.मंत्री ढेबर भाई को सौराष्ट्र से बुलाकर कांग्रेसाध्यक्ष पद संभलवाया था।**
- **इसी प्रकार 1963 में तमिलनाडू के मु.मंत्री का पद छोड़कर के. कामराज ने दिल्ली आकर कांग्रेसाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली थी।**

कांग्रेस अध्यक्ष पद आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में कुल मिलाकर 42 वर्ष गांधी परिवार के पास रहा है तथा गैर-गांधी नेताओं के पास यह पद 33 वर्ष रहा है। सीताराम केसरी ऐसे अंतिम गैर-गांधी नेता थे, जिन्होंने शरद पवार तथा राजेश पायलट को चुनाव में हराकर 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था।

सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पदभार 1998 में ग्रहण किया था तथा वे इस पद पर, 2017 से 2019 तक की अल्पावधि के अलावा लगातार बनी हुई हैं। ज्ञातव्य है कि 2017 से 2019 तक राहुल गांधी इस पद पर रहे थे। 1948 के बाद बने 16 कांग्रेस अध्यक्षों में से पाँच अध्यक्ष गांधी परिवार से रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा लम्बे समय तक पार्टी अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष रहे गैर-गांधी नेताओं में शामिल प्रमुख नाम हैं- नीलम संजीवा रेड्डी, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ तथा पी.वी. नरसिम्हा राव।

पार्टी अध्यक्ष बनने के लिये मुख्यमंत्री पद छोड़ देने वालों में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा (1968-69) भी शामिल हैं। लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था, जिसका उन्हें अफसोस रहा। जैसा कि निजलिंगप्पा ने अपनी आत्मकथा "माइ लाइफ एंड पॉलिटिक्स" में लिखा है: "कई कारणों से, मुझे उस निर्णय पर आज भी अफसोस होता है। अगर मैं मैसूर का मुख्यमंत्री बना रहता तथा मैंने (अध्यक्ष पद की) दुर्वह जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया होता, तो हर नजरिये से मेरे लिये बेहतर रहता।" बहुत वर्ष पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री यू.एन. ढ़ेबर को 1954 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। जहाँ तक ढ़ेबर का मामला है, उस समय यह सुविदित था कि सौराष्ट्र का बम्बई में विलय हो जायेगा और 1956 में ऐसा हो भी गया था। तमिलनाडु के के. कामराज भी 1963 में मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा उन्होंने मुख्यमंत्री पद एम. भक्तवत्सलम को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि कामराज तमिलनाडु के अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।